



मानव संसाधन विकास मंत्रालय
Ministry of Human Resource Development



4 वर्ष
शिक्षा के क्षेत्र में
आमूल परिवर्तन
2014-2018

सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा



MHRD

भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय

शास्त्री भवन, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली – 110001

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शिक्षा क्षेत्र में कई परिवर्तनकारी बदलाव किए गए हैं। इनमें गुणवत्ता, उपलब्धता, जवाबदेही और समता के साथ अनुसंधान एवं नवीनीकरण पर विशेष बल दिया गया है।

प्रकाश जावडेकर



श्री प्रकाश जावडेकर
माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री

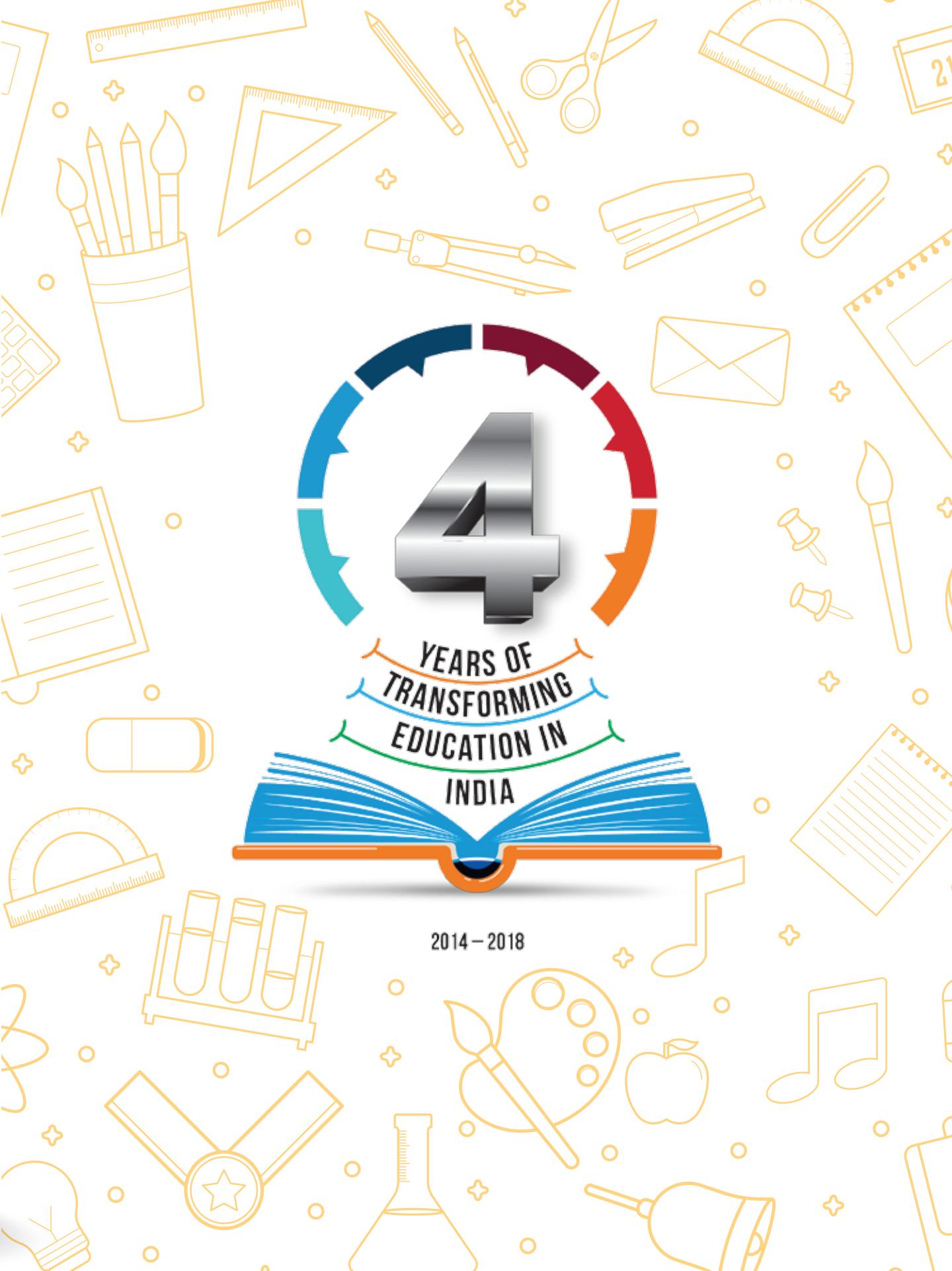


डॉ. सत्यपाल सिंह
माननीय राज्यमंत्री,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय



श्री उपेंद्र कुशवाहा
माननीय राज्यमंत्री,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय

सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा



शिक्षा का मापदंड

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम की स्वीकृति के पश्चात् शिक्षा के मापदंडों को पहली बार परिभाषित किया गया।
- शिक्षा के यह मापदंड विषय तथा कक्षा में अर्जित की जाने वाली छात्रों की क्षमताओं को प्रत्येक वर्ष निरूपित करते हैं।
- शिक्षा के मापदंडों का सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है और उन पर अध्यापक प्रशिक्षण आयोजित किया गया है।
- इससे स्कूलों, अध्यापकों, छात्रों और साथ ही साथ माता-पिता की जवाबदेही में वृद्धि होगी तथा स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।



प्रसार एवं विस्तार

- 15.35 लाख स्कूल, 26 करोड़ छात्र, 86.9 लाख शिक्षक।
- 103 केंद्रीय विद्यालय शुरू किए गए।
- 62 नए नवोदय विद्यालयों की स्थापना।



राष्ट्रीय मूल्यांकन सर्वेक्षण

www.mhrd.gov.in/NAS

- देश के सभी जिलों में राष्ट्रीय शैक्षिक मूल्यांकन सर्वेक्षण आयोजित किया गया जो पूरे विश्व में इस प्रकार का सबसे बड़ा कार्यक्रम था।
- नवम्बर, 2017 में कक्षा में कक्षा 3, 5 और 8 के 22 लाख छात्रों का एक दिन में वैज्ञानिक आधार पर मूल्यांकन किया गया।
- इसी प्रकार फरवरी, 2018 में एक ही दिन में कक्षा 10 के 15 लाख से ज्यादा छात्रों का मूल्यांकन किया गया।
- प्रत्येक जिले में 3, 5 और 8 स्तर के लिए जिला रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया जिसे मुख्य मंत्रियों, संसद सदस्यों तथा अधिकारियों आदि सहित सभी संबंधित घटकों के साथ साझा किया गया।
- यह स्कूल शिक्षा को आंकने तथा इसमें सुधार करने हेतु कार्यनीतियां बनाने में मार्गदर्शक होगा।



अध्यापक प्रशिक्षण

www.nios.ac.in | www.swayam.gov.in

- लगभग 14 लाख अध्यापक जिनको अहर्ता प्राप्त नहीं थी उनको “स्वयम्” प्लेटफॉर्म पर प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा के लिए नामांकित किया गया है, जहां उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उनकी शैक्षिक उपलब्धियों की प्रत्येक स्पष्टाह जांच की जाती है।
- यह विश्व में अपनी तरह का सबसे बड़ा कार्यक्रम है।
- ये प्रशिक्षित और सुयोग्य अध्यापक प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करेंगे।



अनुत्तीर्ण न करने की नीति में परिवर्तन

- विभिन्न राज्यों की मांग पर आरटीई अधिनियम में संशोधन हेतु संसद में एक विधेयक पेंश किया गया है, जो राज्यों को कक्षा 5 एवं 8 के छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित करने की अनुमति देता है।
- इन कक्षाओं में यदि छात्र प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण होने में असफल होता है तो उसे दूसरे प्रयास में सफल होने का अवसर दिया जाता है और यदि छात्र दूसरे प्रयास में भी असफल रहता है तो उसे उसी कक्षा में रख कर पुनः शिक्षित किया जा सकेगा।
- इससे छात्रों द्वारा निरंतर अध्ययन सुनिश्चित होगा और राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अंतर्गत उनके कार्य क्षमता में सुधार होगा।

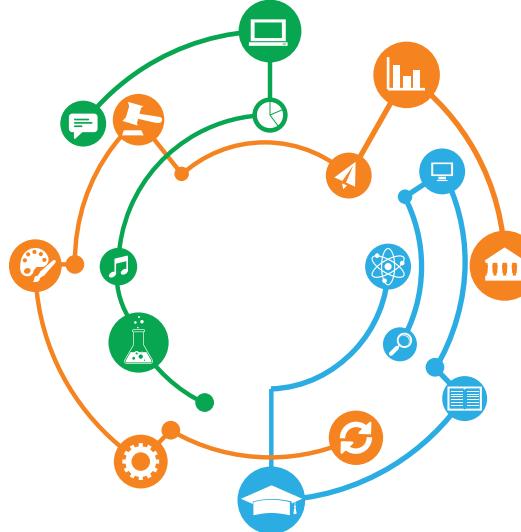
पाठ्यक्रम में सुधार

www.ncert.nic.in



■ शिक्षा का मूल उद्देश्य अच्छा और योग्य नागरिक बनाना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु छात्रों को मूल्यपरक शिक्षा, प्रायोगिक ज्ञान, जीवन कौशल शिक्षा, सृजनात्मक कौशल तथा शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। वर्तमान में इन सभी कार्यकलापों के लिए बिल्कुल भी समय उपलब्ध नहीं है क्योंकि छात्रों पर पाठ्यक्रम का भार अत्यधिक बढ़ गया है। शिक्षाविदों का भी मानना है कि रट्टे मार के सीखना शिक्षा नहीं है, बल्कि शिक्षा पाठ को समझाना, उसको समझाने की कला प्राप्त होना और विश्लेषणात्मक क्षमताओं को बढ़ाना है।

- अतः एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रम के सुधार तथा इसके भार को कम करने का निर्णय लिया है और सभी संबंधित घटकों से इस हेतु उनके बहुमूल्य सुझाव मांगे हैं।
- इस घोषणा के उपरांत माता-पिता, शिक्षाविदों, अध्यापकों और अन्य संबंधित घटकों से बहुत ही अच्छे सुझाव प्राप्त हुए हैं।
- 37 हजार लोगों ने अपने विभिन्न सुझाव दिए हैं जो विशेषज्ञों के विचारधीन हैं।



समग्र शिक्षा

- स्कूल शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजनाओं में आमूल परिवर्तन कर सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान तथा अध्यापक प्रशिक्षण की अलग-अलग योजनाओं को सम्मिलित कर के सुधार किये गये और समग्र शिक्षा नामक नई एकीकृत योजना अनुमोदित की गई है।
- समग्र शिक्षा पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक की शिक्षा को एक दायरे में लाती है।
- इस योजना के लिए समग्र बजट में प्रत्येक वर्ष 20% की वृद्धि की गई है। यह बजट वर्ष 2017–18 में 28,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2018–19 में 34,000 करोड़ रुपये हो गया है तथा वर्ष 2019–20 में 41,000 करोड़ रुपए का अनुमान है।

- समाज के वंचित वर्ग की लड़कियों के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के छात्रावास, जो पहले कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा के लिए ही उपलब्ध थी, उसे अब 12वीं कक्षा तक की शिक्षा के लिए बढ़ाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 3,700 से अधिक ऐसे आवासीय विद्यालयों का बहुत बड़ा विस्तार होगा, जो कक्षा 12 तक निर्बाध शिक्षा प्रदान करेगा।
- प्रत्येक स्कूल को प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक के लिए “पढ़े भारत—बढ़े भारत” अभियान के अंतर्गत पुस्तकालय हेतु 5000 रु. –20,000 रु. का वार्षिक अनुदान दिया जाएगा।





- प्रत्येक स्कूल को “खेले इंडिया—खिले इंडिया” अभियान के तहत खेल संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए 5,000 रु. से 25,000 तक का वार्षिक अनुदान मिलेगा।
- एकमुश्त अनुदान, 14,000 रु. – 50,000 रु. के वर्गसीमा से बढ़कर 25,000 रु. – 1,00,000 रु. के वर्गसीमा तक हो जाएगा।
- विद्यालयों के स्वच्छता के लिए भी निधि आरक्षित की गई है।
- राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, प्रखंड संसाधन केन्द्र और समूह संसाधन केन्द्र जैसी अध्यापक प्रशिक्षण की संस्थाओं को और अधिक वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- उन स्कूलों में जहां छोटे-छोटे स्कूलों को एक जगह लाया गया है, वहां विद्यार्थियों को परिवहन शुल्क के रूप में 6000 रु. प्रति विद्यार्थी सहायता दी जाएगी।
- विशेष दिव्यांग श्रेणी की छात्राओं को 200 रु. का मासिक भत्ता दिया जाएगा।



अटल टिंकरिंग लैब्स

www.aim.gov.in/atal-tinkering-labs.php

- स्कूल विद्यार्थियों में अभिनव कौशलों का विकास करने के लिए 20 लाख रुपए प्रति लैब की लागत पर 2,400 अटल टिंकरिंग लैब स्वीकृत की गई है।
- इन लैबों में 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस उपलब्ध कराई गई है।
- इन लैबों का पहला ओलिम्पीयाड आयोजित किया गया जिसमें हज़ारों विद्यार्थियों ने अपने विचार और प्रयोग प्रस्तुत किए।

मध्याह्न भोजन योजना

www.mdm.nic.in

- भारत के स्कूलों में विश्व की सबसे बड़ी मध्याह्न भोजन योजना चलाई जा रही है जहाँ हर रोज़ 11.4 लाख स्कूलों में 9.5 करोड़ विद्यार्थियों को 17,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की लागत पर ताजा भोजन परोसा जाता है।
- केंद्रीय सरकार द्वारा भोजन पकाने, परिवहन लागत और साथ ही भोजन के गुणवर्धन के लिए और अधिक निधि देने की योजना है।
- इसका परिणाम यह हुआ है कि विद्यार्थियों में एकाग्रता बढ़ी और उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है।



छात्राओं के लिए पृथक शौचालय

- प्रधान मंत्री महोदय की घोषणा के पश्चात् छात्राओं के लिए पृथक शौचालयों का निर्माण करने हेतु मिशन मोड में एक विशेष अभियान को शुरू किया गया। एक वर्ष के भीतर छात्राओं के लिए 1.9 लाख शौचालयों सहित कुल 4 लाख 17 हजार शौचालय उपलब्ध कराए गए तथा स्कूल शौचालयों के रख-रखाव और अनुरक्षण के लिए समग्र शिक्षा के तहत कम्पोजिट स्कूल अनुदान का एक विशेष घटक निर्धारित किया गया है।
- इससे छात्राओं द्वारा स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने में कमी हुई है और कक्षा में एकाग्रता और बढ़ी है।



विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थी

- विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए 54,000 रैंपों और रेलिंग का निर्माण किया गया और 50 हजार विशेष शौचालयों का निर्माण किया गया।



डिजीटल पहल

- आपरेशन डिजीटल बोर्ड: 9वीं कक्षा से राज्यात्मकतर तक 15 लाख शिक्षण कक्षों को 5 वर्ष के भीतर इंटरैक्टिव डिजीटल बोर्ड प्राप्त होंगे, जहां वे सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों/प्रोफेसरों से व्याख्यान प्राप्त कर सकेंगे और विषय पर एक लघु फिल्म देख सकेंगे।
- इससे शिक्षण सुधार कार्यक्रम में क्रांति आएगी। कक्षाएं 'पिलप कक्षा' बन जाएंगी और शिक्षक विद्यार्थियों के साथ और अधिक बातचीत कर पाएंगे।
- इससे संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया, समझ और आकलन में वृद्धि होगी और यह शिक्षा को और अधिक अर्थपूर्ण बनाएगी।
- योजना का रोडमैप तैयार करने और डिजीटल बोर्डों के लिए निम्नतम कीमतें (जिस प्रकार एलईडी बल्बों के मामले में भारत की उपलब्धि रही) सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।
- शगुन (www.ssa.nic.in) रिपॉजिटरी पोर्टल, वीडियो केस अध्ययन, चित्रों और प्रमाण-पत्रों के रूप में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से

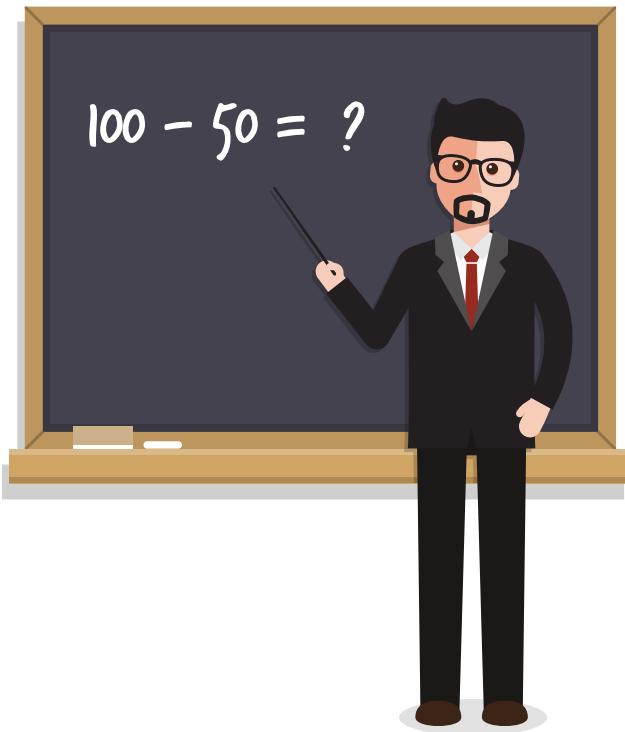


सर्वोत्तम पद्धतियों को ग्रहण करता है। इससे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच साझेदारी और अधिगम में वृद्धि हुई है।

- ई-पाठशाला (www.epathshala.nic.in):— डिजीटल प्रारूप में एनसीईआरटी किताबें सभी के लिए निःशुल्क उपलब्ध हैं। 15 लाख विद्यार्थियों ने ई-पाठशाला एप डाउनलोड किया है और इसे देखने वालों की संख्या 1 वर्ष में 3 करोड़ पार कर चुकी है।

- समग्र शिक्षा के तहत स्कूलों में डिजीटल उपकरणों के लिए अनुदान में वृद्धि हुई।

- अध्यापकों के लिए 'दीक्षा मंच' (www.diksha.gov.in), सभी श्रेणियों के अध्यापकों के क्षमता वर्धन में सुधार लाता है। इससे 50 लाख से अधिक अध्यापकों को शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने में सहायता मिलेगी। अध्यापक, पोर्टल पर अपनी स्वयं की सामग्री अपलोड कर सकते हैं, जो आनलाईन पाठ्यक्रम भी प्रदान करेगा, सर्वोत्तम विषय-वस्तु को साझा करने की अनुमति देगा, प्रगति की मॉनिटरिंग करेगा और क्यूआर कोड के साथ स्फूर्तिदायक पाठ्यपुस्तकों शामिल करेगा।



एकीकृत बी.एड.

- अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की तरह ही, 4 वर्षीय एकीकृत बीए-बीएड और बीएससी-बीएड कार्यक्रम उन विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा जो अध्यापक बनना चाहते हैं। इस सुधार पर चर्चा हुई थी पर इसका कार्यान्वयन कभी नहीं किया जा सका।
- इसके शैक्षणिक वर्ष 2019–20 से शुरू होने की आशा है।
- इससे, ऐसे अभिप्रेरित अध्यापक आएंगे, जो तंत्र में अपनी इच्छा से शामिल हुए हैं। इससे संपूर्ण शिक्षण-अधिगम अनुभव बेहतर होगा।



स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार

www.swachhvidyalaya.com



- स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्रतियोगिता वर्ष 2017 से शुरू हुई। पहले ही वर्ष में 2.5 लाख सरकारी स्कूलों ने ऑनलाईन भाग लिया। समग्र सफाई, पेयजल प्रणाली, शौचालय और शिक्षण-कक्ष की सफाई के लिए स्कूलों का निरीक्षण किया गया था।
- इस वर्ष 6 लाख सार्वजनिक और निजी स्कूलों ने प्रतियोगिता में भाग लिया है।



- इसके परिणामस्वरूप छात्रों के बीच स्वच्छता के बारे में एक व्यापक अनुभूति विकसित हुई है, और यह स्वच्छ संस्कृति बनाये रखने में बहुत सफल होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक छात्र "स्वच्छग्राही" बनने के लिए प्रोत्साहित हो।
- एक भारत—श्रेष्ठ भारत विभिन्न राज्यों के विविध संस्कृतियों के बीच आपसी समझ और भाईचारे के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु पूरे देश में लागू की गई एक अंतर—मंत्रालयी और अखिल भारतीय पहल है।
- 35 राज्य एक—दूसरे के साथ जोड़े गए हैं और वे विभिन्न राज्यों के संस्कृति, त्यौहार, भोजन, रीति—रिवाज, प्रथाओं, साहित्य एवं भाषा को समझने के लिए विभिन्न आदान—प्रदान कार्यक्रमों का संचालन करते हैं।
- सैकड़ों पारस्परिक आदान—प्रदान कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है जहां एक राज्य के लोग उत्सव भाव से भागीदार राज्य की भाषा बोलने, भोजन तैयार करने और खाने, उत्सव मनाने और पोशाक पहनने का प्रयास करते हैं। इसके तहत

एक भारत - श्रेष्ठ भारत

www.ekbharat.gov.in

जम्मू एवं कश्मीर के छात्र तमिलनाडु गये और वहाँ के छात्रों से घुले—मिले।

■ इसके परिणामस्वरूप बेहतर समझ, मूल्यांकन और एक दूसरे की जीवन शैली और मानसिकता की जानकारी हुई है। यह राष्ट्रीय सौहार्द के लिए एक सशक्त आधार बना है।



परीक्षा पर चर्चा

'परीक्षा पर चर्चा' नामक एक अनूठे पहल में, प्रधानमंत्री महोदय ने फरवरी, 2018 में परीक्षा तनाव के विषय पर देश के उच्च विद्यालय और कॉलेज के छात्रों से बातचीत की। इस कार्यक्रम में प्रश्नों और विचारों का एक बहुत ही जीवंत आदान-प्रदान देखा गया था जिसे लगभग 7 करोड़ छात्रों और दर्शकों द्वारा देखा या सुना गया। इस प्रकार सबसे बड़े देखे जाने वाले कार्यक्रमों में यह एक कार्यक्रम बन गया। इस कार्यक्रम का प्रारूप टाउन हॉल शैली में था और बातचीत की ताजगी और स्वाभाविकता का न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी कई लोगों ने पसंद किया। इसलिए इस कार्यक्रम में सोशल मीडिया पर भी दर्शकों की संख्या सबसे अधिक देखी गई।



स्कूलों की संख्या एवं भर्ती

संपूर्ण देश में स्कूलों की संख्या 2012–13 में 14.9 लाख से बढ़कर 2016–17 में 15.35 लाख हुई। स्कूलों में भर्ती की संख्या 2012–13 में 25.42 करोड़ से बढ़कर 2015–16 में 26 करोड़ से ऊपर पहुँच गई है।



प्रसार एवं विस्तार

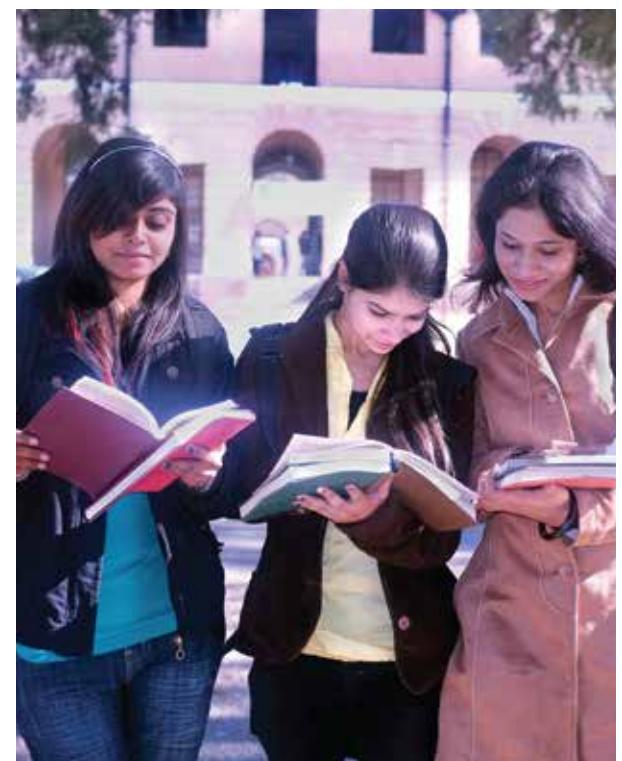
- 141 विश्वविद्यालय, 7 आईआईटी, 7 आईआईएम, 14 आईआईआईटी एवं 1 एनआईटी की स्थापना तथा परिचालन।
- कुल 864 विश्वविद्यालय एवं 42,000 कॉलेज में पढ़ रहे 3.7 करोड़ छात्र आज उत्तम शिक्षा का लाभ उठा रहे हैं।



बजट और हेफा

www.hefa.co.in

- उच्चतर शिक्षा वित्तीय एजेंसी (हेफा) के नए मॉडल के साथ, शिक्षा के कुल बजट में असाधारण वृद्धि हुई। हेफा उच्चतर, स्कूल और चिकित्सा शिक्षा में शोध, शैक्षिक आधारभूत संरचना निर्माण एवं विस्तार के लिए कर्ज देगा।
- अवसंरचना परियोजनाओं को शुरू करने में अधिक समय और लागत को समाप्त करने में एवं परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने में हेफा शैक्षणिक संस्थानों की सहायता करेगा। हेफा देश में शिक्षा और शोध हेतु अच्छी सुविधाएं प्रदान करेगा।
- इसे “2022 तक शिक्षा की अवसंरचना और प्रणाली की पुनर्रचना” पहल के तहत कार्यान्वित किया गया। हेफा ऋण के रूप में 4 वर्षों में 1,00,000 करोड़ रुपए प्रदान करेगा।
- शिक्षा हेतु सम्पूर्ण वित्तीय उपलब्धता 2013–14 में 65,867 करोड़ रुपए से 2018–19 में 1,10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ा है।
- दिए गए ऋण की वापसी कुछ संस्था द्वारा और कुछ सरकार द्वारा की जाएगी।
- हेफा के माध्यम से शैक्षिक अवसंरचना को ऋण देने से छात्रों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं आयेगा।



स्वायत्तता



- अच्छे संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान कर, आईआईएम विधेयक को पारित कर, ग्रेडेड स्वायत्तता प्रदान कर और 20 विश्वस्तरीय संस्थानों की स्थापना कर मोदी सरकार ने शिक्षा में आमूल सुधार सुनिश्चित किया।
- भारतीय प्रबंध संस्थानों को संस्थान चलाने और सरकारी हस्तक्षेप और नियामक मार्गविरोध के बिना विश्व रैकिंग में बेहतर करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता देने हेतु आईआईएम विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया। इस सुधार पर काफी समय से विचार चल रहा था परंतु प्रत्यक्ष काम पिछले वर्ष किया गया।
- अधिनियम हेतु नियम तैयार किए जा रहे हैं और जुलाई, 2018 तक कार्यान्वित किए जाएंगे।
- सरकार ने चैलेंज मोड में 20 संस्थानों के चयन को अंतिम रूप दिया है जिन्हें ‘प्रतिष्ठित संस्थान’ के रूप में घोषित किया जाएगा। इन संस्थानों को एक दशक में विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय (पहले 500 रैंक में) बनने के लिए पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। लक्ष्य प्राप्ति
- गुणवत्ता युक्त संस्थान के लिए स्वयत्ता प्रदान करने हेतु उठाए गए सभी अभूतपूर्व कदम भारतीय संस्थाओं को विश्व में मान्यता और उच्च स्तरीय रैंकिंग प्राप्त करने में सहायता करेंगे।



गुणवत्ता के लिए वित्तीय सहायता

■ मोदी सरकार का जोर हमेशा सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने पर होता है। इस दिशा में रुसा, टैक्विप, ज्ञान, एनआईआरएफ और नैक सुधार मुख्य पहल हैं।

■ **रुसा (www.rusa.nic.in) के तहत** शिक्षण और अनुसंधान में गुणवत्ता सुधार के लिए अनेक विश्वविद्यालयों (117) और कॉलेजों (1250) को अनुदान प्रदान किया गया है। रुसा—2 को अनुमोदित कर दिया गया है। इसके तहत, राज्य में उच्चतर शिक्षण संस्थाओं के गुणवत्ता सुधार हेतु वार्षिक बजट में रुसा—1 के तहत 2600 करोड़ रुपये के मुकाबले रुसा—2 में 7101.02 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 115 आकांक्षित जिलों में 70 नए मॉडल कॉलेज स्वीकृत किए जा रहे हैं और 75 कॉलेजों को स्तरोन्नत किया जाएगा।

■ **छात्रवृत्तियों और अध्येतावृत्तियों के तहत** इस सरकार ने यूजीसी के छात्रवृत्तियों और

अध्येतावृत्तियों की राशि को 55 प्रतिशत तक बढ़ाया है। वर्ष 2008–09 से 2013–14 के दौरान 2016.85 करोड़ रुपये की कुल राशि की तुलना में वर्ष 2014–15 से 2017–18 तक 5162.93 करोड़ रुपये वितरित किए गए। इस सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए नई छात्रवृत्तियों/अध्येतावृत्तियों को सहायता प्रदान की, भाषा और बालिका अध्येतावृत्तियों सहित मानविकी में अनुसंधान को प्रोत्साहन प्रदान किया। **जम्मू और कश्मीर** के 5000 छात्रों को छात्रवृत्ति के तहत सालाना 1.30 लाख रु. से 4 लाख रु. तक का वजीफा दिया जाता है। इससे उनके शिक्षा, छात्रावास और अन्य व्यय का निर्वहन हो जाता है। अधिसंचयक कोटा का सृजन करके प्रतिभा के आधार पर उनका चयन किया जाता है और उन्हें बेहतर व्यावसायिक कॉलेजों में दाखिला दिया जाता है। इससे गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्राप्त करने में जम्मू और कश्मीर के हजारों छात्रों को सहायता मिली है।



■ टैक्विप (www.npiu.nic.in/TEQIPIII)

तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता सुधार का कार्यक्रम है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड जैसी पहाड़ी राज्यों, 8 पूर्वोत्तर राज्यों, अंडमान निकोबार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखण्ड और असम को अगले 3 वर्षों में चरण—3 के तहत 2600 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। यह तकनीकी शिक्षा में क्षेत्रीय अंतर को पाठने में मदद करेगा। **1200 आईआईटी** और एनआईटी के स्नातक 3 वर्षों तक शैक्षणिक रूप से पिछड़े जिलों में पढ़ाएंगे। वे 53 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ाएंगे जहां विभागों में रिक्तियां अधिक हैं। इस प्रकार 1 लाख विद्यार्थी गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्राप्त करेंगे जिससे वे आज तक वंचित थे।

■ ज्ञान (www.gian.iitkgp.ac.in) के तहत

अब तक 58 देशों से 700 प्रोफेसरों ने भारतीय उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं में विद्यार्थियों के लिए विशेषज्ञता प्राप्त विषयों में 1117 पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक व्यवस्था से 40 हजार से अधिक विद्यार्थी और संबद्ध भारतीय संकाय लाभान्वित हुए हैं। वर्ष

2018–19 में 60 देशों से 800 प्रोफेसरों को विभिन्न संस्थाओं में विभिन्न पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए जोड़ा गया है। इन पाठ्यक्रमों में से अधिकांश पाठ्यक्रम स्वयम् मंच पर रिकार्ड किए गए हैं और अपलोड किए जा रहे हैं।

■ **एनआईआरएफ (राष्ट्रीय सांस्थनिक रैंकिंग कार्यालय)** (www.nirfindia.org) मोदी सरकार की एक बड़ी पहल है जहां कॉलेज और विश्वविद्यालय को उनके समग्र निष्पादन और गुणवत्ता पर रैंक प्रदान किया जाता है। यह इस पहल का तीसरा वर्ष है और इसमें 4500 से अधिक संस्थाओं ने भाग लिया है। यह गुणवत्ता का मापदंड बन गया है और संस्थाओं में प्रतिस्पर्धात्मक भावना पैदा करता है।

■ नैक सुधार (www.naac.gov.in)

मोदी सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं के मूल्यांकन और प्रत्यायन में आमूल परिवर्तन हुआ है। इससे प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित हुई है। 70 प्रतिशत मूल्यांकन डाटा संग्रह के माध्यम से होता है जिसके बाद तृतीय पक्ष वैधीकरण किया जाता है।

डिजिटल पहल



■ स्वयम्, स्वयम् प्रभा, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, राष्ट्रीय शैक्षिक डिजिटल संग्रह और वाई-फाई कैपेंस कुछेक डिजिटल पहलों हैं जो शिक्षा क्षेत्र का विस्तार करने और गुणवत्ता सुधारने में सफल रहा है।

■ स्वयम् (www.swayam.gov.in) भारत का देश में विकसित मूक (व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम) है। यह इंटरएक्टिव पाठ्यक्रमों के लिए एक एकीकृत मंच है। छात्रों, शिक्षकों, पेशेवरों और अन्य किसी व्यक्ति (जो अपने कौशल और अहंताओं को बेहतर करना चाहता हो) के लिए 1032 पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। यह व्याख्यान, सामग्री, ट्यूटोरियल, इंटरेविटव सत्र, परीक्षाओं और प्रमाणन का एक संपूर्ण पैकेज है। यह सभी जगह, किसी के लिए और कहीं भी उपलब्ध निःशुल्क शिक्षा है। शुरूआती दौरे के अंतिम 10 माह में इस पहल को 20 लाख से अधिक पंजीकरण के साथ जबरदस्त समर्थन

प्राप्त हुआ है। छात्रों को 20 प्रतिशत क्रेडिट ट्रांसफर की अनुमति है।

■ स्वयम् प्रभा (www.swayamprabha.gov.in) – यह डीटीएच प्लेटफार्म पर 32 समर्पित उच्च गुणवत्तायुक्त शैक्षणिक चैनलों का एक समूह है जोकि दूरदर्शन की निःशुल्क डिश के माध्यम से उपलब्ध है। कई टेलीफोन आपरेटर भी अपनी प्रणाली के माध्यम से इन चैनलों को प्रसारित कर रहे हैं। इन चैनलों के माध्यम से देश के किसी भी भाग में कोई भी इंटरनेट के बगैर उत्कृष्ट शिक्षकों द्वारा दिए गए व्याख्यान देख सकता है। यह यूट्यूब पर अभिलेखीय विवरण के रूप में भी उपलब्ध है।

■ एनडीएल – राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय 1 करोड़ 70 लाख पुस्तकों और रिकार्डिंग का एक ऑनलाइन पुस्तकालय है जोकि पंजीकृत उपयोगकर्ता के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। यह

ई-कंटेंट की एक राष्ट्रीय रिपोजिटरी भी है। यह शैक्षिक संस्थानों में मौजूदा सारी डिजिटलीकृत सामग्री को समीकृत करता है। इसके 32 लाख पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं और इसकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसने छात्रों और संकाय को अत्यधिक लाभान्वित किया है। अब उन्हें एक अपेक्षित पुस्तक की खोज में एक पुस्तकालय से दूसरे पुस्तकालय में भटकना नहीं पड़ेगा। सभी पुस्तकालय उसके लैपटॉप/मोबाइल पर उपलब्ध हैं।

■ एनएडी – राष्ट्रीय शैक्षिक डिजिटल संग्रह (www.ndl.iitkgp.ac.in) है जहां सभी शैक्षिक दस्तावेजों जैसे, अंकतालिका, प्रमाणपत्र को डिजिटल रूप से संरक्षित किया जाता है। आसंभ के नौ महीनों के भीतर ही 1.05 करोड़ से अधिक दस्तावेजों को डी-मैट फार्मेट में संरक्षित कर दिया गया है। अतः छात्रों को अपनी प्रतिलिपियों के लिए इधर-उधर भटकने की

आवश्यकता नहीं होगी और छात्रों तथा नियोजकों को एक क्लिक पर प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध होंगे। इस प्रकार, चोरी या दस्तावेज जालसाजी का खतरा भी दूर हो जाता है।

■ वाई-फाई : सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को वाई-फाई सुविधा प्रदान की गई है। यूजीसी द्वारा समर्थकारी प्रावधानों ने कैंपसों को वाई-फाई बनाने में गति प्रदान की है। लगभग 400 विश्वविद्यालय परिसर और 10,000 कॉलेज वाई-फाई से लैस हैं।



अध्यापक प्रशिक्षण

पीएमएमएनएमटीटी (पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण मिशन) (www.mhrd.gov.in/pmmmnmtt) ने 1 लाख से अधिक कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित किए हैं। महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में अध्यापकों के प्रशिक्षण का यह पहला व्यापक कार्यक्रम है। नए नियुक्त किए गए शिक्षकों को 6 माह का शिक्षा-शास्त्र संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे विद्यार्थियों में अपनी अच्छी पैठ बना सकें और गुणवत्ता में सुधार कर सकें।



अनुसंधान और नवाचार पहल



- **इंप्रिट (www.imprint-india.org)** – आईआईटी और एनआईटी उन 10 क्षेत्रों में शोध प्रोत्साहित करता है, जिनका समाज में सर्वाधिक महत्व है। इसके तहत, शोध प्रस्तावों को प्रतिस्पर्धा के आधार पर सार्वजनिक वित्तपोषण किया जाता है। 323 शोध परियोजनाएं प्रक्रियाधीन हैं। इंप्रिट-2 को भी शुरू किया गया है और नए प्रस्ताव के आकलन की प्रक्रिया जारी है। यह समाज में एक शोध संस्कृति तैयार करेगी और डोमेन क्षेत्रों में फोकस शोध को बल मिलेगा।
- **यूएवाई – (उच्चतर आविष्कार योजना)** यह उद्योग-शिक्षा साझेदारी की प्रथम मुख्य पहल

है। आईआईटी में संकाय और छात्रों के दलों द्वारा समाधान ढूँढ़ने के लिए 98 परियोनाएं शुरू की गई हैं जोकि उद्योग की आवश्यकतानुकूल हैं। यह छात्रों और संकाय को व्यावहारिक शोध का अवसर देता है जोकि शिक्षा को समृद्ध बनाती है।

■ **पीएमआरएफ – प्रधानमंत्री शोध फेलोशिप (www.pmrf.in)** देश में उत्कृष्ट प्रतिभाओं को उत्कृष्ट शोध सुविधा, उचित माहौल और उदार फेलोशिप प्रदान करता है। इसके तहत शैक्षिक उत्कृष्टता वाले 1000 छात्रों को पांच वर्षों तक 70,000 रुपये – 80,000 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति और पीएच.डी शोध के लिए 2 लाख रुपये वार्षिक शोध का अनुदान दिया जाता है।



- **विभिन्न आईआईटी परिसरों में 6 अनुसंधान पार्क और पोषण केन्द्र स्थापित किए हैं ताकि उद्योग के साथ अनुसंधान वातावरण और गहन जुड़ाव का सृजन किया जा सके।**
- **स्मार्ट इंडिया हैकाथन (www.aicte-india.org/Initiatives/smart-india-hackathon)** भारत में 40,000 छात्रों की उत्साहवर्धक भागीदारी के साथ 2017 में आयोजित हुआ था। हैकाथन जनता द्वारा सामना की जा रही विभिन्न समस्याओं के डिजिटल समाधानों को प्राप्त करने की एक

प्रतिस्पर्धा है। पिछले वर्ष 600 समस्या विवरण दिए गए थे। 6 छात्रों का एक दल चुनी गई समस्या पर तीन महीने के लिए कार्य करता है और डिजिटल समाधान निकालता है। 54 से अधिक समाधान योजना स्तर पर हैं। वर्ष 2018 में, 1,00,000 छात्रों ने भाग लिया था। हैकाथन इंजीनियरी छात्रों के लिए कार्य और अनुसंधान का अवसर प्रदान करता है। इस वर्ष हार्डवेयर हैकाथन भी आयोजित हुआ है। भारत का हैकाथन दुनिया का सबसे बड़ा हैकाथन साबित हुआ है।



समता पहल

- उदार शैक्षिक ऋण, शिक्षा ऋणों पर ब्याज सब्सिडी, छात्रवृत्ति प्रत्याभूति पहलों के तहत कोई भी गरीब प्रतिभाशाली छात्र उच्चतर शिक्षा से वंचित नहीं होगा।
- वर्ष 2014 से, शिक्षा ऋणों पर 1800 करोड़ रु. प्रतिवर्ष की ब्याज सब्सिडी, 7.6 लाख छात्रों को दी गई है। अगले तीन वर्षों के लिए बजट 2,200 करोड़ रु. प्रति वर्ष तक बढ़ गया है और यह दस लाख छात्रों को शामिल करेगा।
- आईआईटी में केवल 8 प्रतिशत बालिकाएं हैं। उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए, एक चार वर्षीय योजना तैयार की गई है जो अगले 4 वर्षों में उनकी भागीदारी 8 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक सुनिश्चित करेगा।



राष्ट्रीय परीक्षण एजेन्सी

राष्ट्रीय परीक्षण एजेन्सी स्थापित की जा चुकी है जो अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार पारदर्शी रूप में सभी व्यावसायिक परीक्षाओं को संचालित करेगी। आज सीबीएसई को 1.5 करोड़ छात्रों के लिए 24 परीक्षाएं संचालित करनी होती है। एनटीए सभी प्रकार की गुणवत्तायुक्त और समयबद्ध परीक्षाएं संचालित करेगा।



उन्नत भारत अभियान



- **उन्नत भारत अभियान (यूबीए)** के अंतर्गत प्रत्येक उच्चतर शैक्षणिक संस्थाएं जैसे आईआईटी, एनआईटी, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कॉलेज 3 से 5 गांवों को अपनाएगा, उनकी समस्याओं को समझेगा और कार्यान्वयन के लिए जिला प्रशासन को समाधान प्रदान करेगा।
- तकनीकी संस्थाएं प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करेगी जबकि गैर-तकनीकी संस्थाएं जागरूकता और बेहतर कार्य प्रणाली के ज्ञान का प्रचार करेंगी।



- अब तक यूबीए के अंतर्गत करीब 750 शैक्षणिक संस्थाओं का नामांकन किया गया है।
- यह कार्यक्रम छात्रों और गांव दोनों को लाभ प्रदान करेगा। छात्र ग्रामीण वास्तविकताओं से वाकिफ होंगे जबकि गांवों संस्थाओं से लाभ प्राप्त करेंगे।
- संपूर्ण भारत में जिला प्रशासन और शैक्षणिक संस्थाओं के बीच एक आवश्यक मजबूत संबंध का विकास होगा।



भारत में अध्ययन

- 18 अप्रैल, 2018 को, विदेशी छात्रों के दाखिले के लिए स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम (www.studyinindia.gov.in) शुरू किया गया। यह भारत को एक आकर्षक शिक्षा मंजिल के रूप में प्रस्तावित करता है। भारत में विदेशी छात्रों को आकर्षित करने के लिए 30 देशों को लक्षित किया जा रहा है। 160 संस्थाएं

(सार्वजनिक और निजी दोनों) चुनी गई हैं। शुरू होने के प्रथम वर्ष में 18,000 सीटें प्रदान की जा रही हैं जिसमें से 50 प्रतिशत से अधिक सीटों पर शुल्क माफ है।

- विदेशी छात्रों की संख्या में वृद्धि होने के अलावा, यह पहल भारतीय संस्थाओं की वैश्विक रैंकिंग में सुधार करने में सहायता करेगी।

